

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1469

दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

तहसीलों और उप-तहसीलों में वर्षामापकों के आधार पर वर्षा से होने वाली क्षति का अनुमान

1469. श्री हनुमान बेनीवाल:

एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार तहसीलों और उप-तहसीलों में स्थापित वर्षामापी यंत्रों के आधार पर अत्यधिक वर्षा या बाढ़ से होने वाली क्षति का आकलन करती है;

(ख) क्या सरकार का लोगों को ऐसी आपदाओं में राहत दिलाने के लिए तहसील और उप-तहसील के साथ-साथ गांवों को भी एक इकाई मानकर या गांवों में भी वर्षामापी यंत्र लगाकर भारी वर्षा से होने वाली क्षति का आकलन करने का प्रावधान करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) नहीं, ज़्यादा बारिश या बाढ़ से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा तहसील और सब-तहसील में लगे रेन गेज से नहीं लगाया जाता है। बाढ़ वाले इलाके का अंदाज़ा लगाने के लिए सैटेलाइट डेटा जैसे रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है और इन नुकसानों और असर का अंदाज़ा लगाने के लिए मैनुअल सर्वे भी किया जाता है। रेन गेज बारिश का अवलोकन अभिलेख करने और भारी बारिश, बहुत भारी बारिश और बहुत ज़्यादा भारी बारिश जैसी बारिश की घटनाओं के हिसाब से बारिश की रिपोर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा अलग-अलग जगहों पर लगाए गए अपने रेन गेज पर लगभग रियल टाइम बेसिस पर देखा गया बारिश का डेटा, सीडब्ल्यूसी द्वारा नदी में बाढ़ का अनुमान बनाने और बाढ़ की निगरानी में मदद करता है।

**लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1469, दिनांक 09.12.2025**

निर्धारित बाढ़ अनुमान स्टेशनों पर नदियों में बाढ़ को नॉर्मल से ऊपर (पानी का लेवल:वॉर्निंग लेवल और डेंजर लेवल के बीच), सीवियर (पानी का लेवल:डेंजर लेवल और सबसे ज़्यादा बाढ़ के लेवल के बीच) और एक्सट्रीम फ्लड (पानी का लेवल:सबसे ज़्यादा बाढ़ के लेवल से ऊपर) कैटेगरी में बांटा गया है। वॉर्निंग और डेंजर लेवल राज्य सरकारें पहचानी गई जगह पर नदी के पानी के लेवल के हिसाब से आस-पास के इलाके में नुकसान के अंदाज़े के आधार पर तय करती हैं, जबकि सबसे ज़्यादा बाढ़ का लेवल आम तौर पर उस नदी की जगह पर पहले देखा गया सबसे ज़्यादा पानी का लेवल होता है।

(ख) नहीं, सरकार का गांवों में रेन गेज लगाकर भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने का कोई प्रावधान करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) बारिश की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए, अभी देश भर में कुल 7900 रेन गेज (आईएमडी -6700 और सीडब्ल्यूसी -1200) काम कर रहे हैं।

\*\*\*\*\*